

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

प्रलिस के लयः

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम 2013, सार्वजनिक वतऱण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशऱन, वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) ।

मेन्स के लयः

भारत की खाद्य सुरक्षा पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) का प्रभाव ।

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) को दसऱंबर 2022 तक (और तीन महीने के लयः) वसऱतारतऱ करने की घोषणा की ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):

■ परिचय:

- 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को **कोवडऱ-19** के वरुद्ध लडऱई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लयः **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (PMGKP)** के हसऱसे के रूप में शुरू कयऱ गया था ।
- इस योजना के तहत **सार्वजनिक वतऱण प्रणाली (PDS)** के माध्यम से पहले से ही प्रदान कयऱ जा रहे 5 कलऱोग्राम अनुदानतऱ खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक वयकऱ को **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA), 2013** के तहत **5 कलऱोग्राम अतरऱकऱत अनाज (गेहूँ या चावल) मुफऱ** में उपलब्ध कराने का लक्ष्य नरऱधारतऱ कयऱ गया है ।
- प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020) की अवधऱ के लयः की गई थी, जसऱमें कुल 80 करोडऱ राशन कार्डधारक शामिल थे । बाद में इसे सऱतऱंबर 2020 तक बढ़ा दयऱा गया था ।
- **वतऱत मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है ।**
- देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से **वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)** योजना के तहत कोई भी प्रवासी श्रमकऱ या लाभार्थी पोर्टेबलऱतऱ के माध्यम से मुफऱ राशन का लाभ उठा सकता है ।

■ **लागत:** सभी चरणों के लयः PMGKAY का कुल खर्च लगभग 91 लाख करोडऱ रुपए होगा ।

■ **चुनौतयऱः** एक प्रमुख मुद्दा यह है कऱ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम के तहत लाभार्थी अंतमऱ जनगणना (2011) पर आधारतऱ है, हालाँकऱतऱब से खाद्य-असुरक्षा से जुडे़ लोगों की संख्या में वृद्धऱ हुई है, जो कऱ अब इस योजना के तहत शामिल नहीं है ।

■ मुद्दे:

- **महँगा:** ससऱते अनाज की प्रचुर आपूर्तऱ की आवश्यकता को बनाए रखना और बढ़ाना सरकार के लयः बहुत महँगा है । वर्ष 2022 में भारत को गेहूँ और चावल के नरऱयात को प्रतऱबऱधतऱ करना पडऱा, क्योंकि अनश्चितऱ मौसम के कारण फसल को नुकसान हुआ, खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ गया, वैश्वकऱ कृषऱ बाजारों में संकट की स्थतऱतऱ देखी गई ।
- **राजकोषीय घाटे में वृद्धऱ:** यह राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक सीमतऱ करने के सरकार के लक्ष्य के लयः जोखमऱ उत्पन्न कर सकता है ।
- **मुद्रासफीतऱ**
- कार्यक्रम में लयः गए नरऱणय मुद्रासफीतऱ को भी प्रभावतऱ कर सकते हैं । चावल और गेहूँ की कीमतें जो कऱ भारत की खुदरा मुद्रासफीतऱ का लगभग 10% हसऱसा है, लू के प्रकोप और अनयऱमतऱ मानसून के कारण इनके उत्पादन में कमी आई है तथा इसी वजह से उनकी कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है ।

सरकार की संबद्ध पहलें:

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशऱन**

- [राष्ट्रीय कृषिविकास योजना \(RKVY\)](#)
- [तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मोटे अनाज पर एकीकृत योजनाएँ \(ISOPOM\)](#)
- [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना](#)
- [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम](#)

??????:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा वधियक ने भारत में भुखमरी और कुपोषण को खत्म करने में कैसे मदद की है? (2021)

स्रोत : द दृष्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-garib-kalyan-anna-yojana-3>

